[2013] 3 एस. सी. आर 359

मो. मेहताब खान और अन्य

बनाम

खुशनुमा इब्राहिम और अन्य।

(2013 की सिविल अपील संख्या 678)

24 जनवरी, 2013

[पी. सतशिवम और रंजन गोगोई, जेजे.]

विनिर्दिष्ट राहत अधिनियम, 1963- एस.6 - का दायरा - आयोजित: धारा 6 के तहत कार्यवाही अवैध बेदखली के मामलों में तत्काल उपचार प्रदान करने के लिए संक्षिप्त कार्यवाही है - निर्णय के लिए स्वामित्व या कब्जे के बेहतर अधिकार का प्रश्न नहीं उठता है।

अंतरिम आदेश: अंतरिम आदेश देना - सिद्धांत, अदालतों को इस संबंध में पालन करना चाहिए, समझाया गया - माना गया: अपीलीय अदालत द्वारा वादी को दी गई अंतरिम राहत, तत्काल मामले में वादी को कब्ज़ा सौंपने के लिए एक अनिवार्य निर्देश है। अनिवार्य अंतरिम राहत के लिए उच्चतम स्तर की संतुष्टि की आवश्यकता होती है, जो निषेधात्मक निषेधाज्ञा देने वाले मामले की तुलना में बहुत अधिक है - जब ट्रायल कोर्ट, पार्टियों के संबंधित मामलों और दस्तावेजों पर विचार करने पर यह

विचार करता था कि वादी एक आदेश का हकदार है अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा गंभीर संदेह में थी, अपीलीय अदालत ट्रायल जज द्वारा विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी जब तक कि ऐसा अभ्यास स्पष्ट रूप से गलत या अस्थिर नहीं पाया गया - अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा।

अपील - विवेकाधीन आदेश के विरुद्ध - अपीलीय अदालत के क्षेत्राधिकार की व्याख्या।

वादी संख्या 1 और 2 ने एक मुकदमा दायर किया। विनिर्दिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के 6। उन्होंने दलील दी कि सूट फ्लैट और सूट कार्यालय पर उनका कब्जा प्रतिवादी 2, 3 और 4 द्वारा जबरन ले लिया गया था। अदालत ने एक रिसीवर नियुक्त किया। रिसीवर की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 5 से 9 के पास सूट फ्लैट का कब्जा पाया गया। फ्लैट का औपचारिक कब्ज़ा रिसीवर द्वारा ले लिया गया था, लेकिन वह सूट ऑफिस पर कब्ज़ा नहीं कर सका। प्रतिवादियों की दलील थी कि वाद संपत्तियों पर वादी का कब्जा नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने वादी के मामले में विसंगतियों और असंभाव्यताओं को देखते हुए, जिन्हें मुकदमे में स्थापित करने की आवश्यकता थी, वादी को मुकदमे की संपत्तियों पर वापस कब्जा करने की अंतरिम राहत से इनकार कर दिया। अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलटते हुए वादी को अंतरिम राहत दी। इसलिए तत्काल अपील दायर की गई।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए

आयोजित: 1. धारा के तहत एक कार्यवाही। विनिर्दिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 6 का उद्देश्य एक सारांश कार्यवाही करना है, जिसका उद्देश्य पीड़ित पक्ष को उस कब्जे को पुनः प्राप्त करने के लिए तत्काल उपाय प्रदान करना है, जिसे बेदखली के एक अवैध कार्य द्वारा उसे अन्यायपूर्ण ढंग से अस्वीकार कर दिया गया हो। धारा 6 के तहत किसी मुकदमे में निर्णय के लिए स्वामित्व या कब्जे के बेहतर अधिकार के प्रश्न नहीं उठते हैं, जहां निर्णय लेने के लिए आवश्यक एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या वादी दाखिल होने की तारीख से छह महीने पहले किसी भी समय कब्जे में था। सुविधाजनक होना। धारा 6 में अंतर्निहित विधायी चिंता अवैध बेदखली के मामलों में त्वरित उपाय प्रदान करना है ताकि वादियों को कानून के क्षेत्र के बाहर उपचार खोजने से हतोत्साहित किया जा सके। यह धारा 6(3) के प्रावधानों से स्पष्ट है जो ऐसे मुकदमे में पारित डिक्री के खिलाफ अपील या यहां तक कि समीक्षा के उपाय पर रोक लगाता है। [पैरा 12) [370-डी-जी]

एल. आर. एस. द्वारा पी. एस. सतप्पन (मृत) वी. आंध्र बैंक लिमिटेड और अन्य (2004) 11 एससीसी 672: 2004 (5) पूरक। एससीआर 188 संदर्भित किया गया।

2. स्थिति की जमीनी हकीकत को देखते हुए, यह विचार करना न तो संभव है और न ही व्यावहारिक है कि अंतरिम मामले, भले ही वे मुख्य मुकदमे के गुणों के साथ अटूट रूप से जुड़े हों, उनका उत्तर हमेशा सख्त तटस्थता बनाए रखते हुए दिया जाना चाहिए, अर्थात् , निर्णय लेने से इंकार करके। इसलिए, अदालतों को उन मुद्दों पर विचार करके अंतरिम मामलों पर निर्णय लेने का साहस करना होगा जो मुकदमे की पूरी सुनवाई में निर्णय के लिए सबसे अच्छे हैं। इस तरह के अभ्यास को करने में अंतर्निहित जोखिम को देखते हुए, जो ज्यादातर मामलों में नाजुक हो जाता है, अदालतों को इस संबंध में कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, हालांकि ऐसे सिद्धांतों को किसी स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूले या किसी सटीक निर्धारित मानदंडों के भीतर नहीं फंसाया जा सकता है। अदालतों को यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि क्या मुख्य मुकदमे में शामिल मुद्दों के अलावा अन्य मुद्दों पर विचार करने पर अंतरिम राहत दी जा सकती है और क्या आंशिक अंतरिम राहत मामले के अंतिम निपटान तक न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी। प्रतिवादी पर निषेधाज्ञा देने के परिणाम, यदि वादी को मुकदमा हारना है, साथ ही वादी पर होने वाले परिणामों के साथ जहां निषेधाज्ञा से इनकार कर दिया जाता है लेकिन अंततः मुकदमा डिक्री हो जाता है, हर मामले में अदालत द्वारा सावधानीपूर्वक तौला और संतुलित किया जाना चाहिए। जहां भी संभव हो अंतरिम राहतें, जो प्री-ट्रायल डिक्री के बराबर होती हैं, से बचना चाहिए। हालाँकि इस आशय की

टिप्पणियाँ और स्पष्टीकरण कि दर्ज किए गए निष्कर्ष प्रथम दृष्टया और अस्थायी हैं, केवल पार्टियों के अंतरिम अधिकार को तय करने के लिए हैं या इरादा है, अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं और मुख्य मुकदमे से संबंधित मुद्दों पर अंतरिम निष्कर्षों का इस प्रक्रिया में एक स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। अंतिम निर्णय के समय, यहीं पर न्यायिक अनुशासन का सख्त अभ्यास काफी मदद और सहायता प्रदान करेगा। आत्म-सुधार की शक्ति और वरिष्ठ मंचों के आदेशों को उचित परिप्रेक्ष्य में समझने से उन मुद्दों पर अंतरिम मामले का निर्णय लेने में निहित खतरों को हल करने में काफी मदद मिलेगी, जिनका मुख्य मुकदमे में उत्पन्न होने वाले मुद्दों के साथ घनिष्ठ संबंध हो सकता है। [पैरा 13] [371-सी-एच; 372-ए-बी]

3. तत्काल मामले में उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ द्वारा वादी को दी गई अंतरिम राहत वादी को कब्ज़ा सौंपने के लिए एक अनिवार्य निर्देश है। अनिवार्य अंतरिम राहत देने के लिए न्यायालय की उच्चतम स्तर की संतुष्टि की आवश्यकता होती है; यह निषेधात्मक निषेधाज्ञा देने वाले मामले से कहीं अधिक है। [पैरा 14) [372-सी-डी]

दोराब कवासजी वार्डन बनाम कूमी सोराब वार्डन और ओआरएस। (1990) 2 एससीसी 117: 1990 (1) एस. सी. आर. 332-पर निर्भर था।

4. ऐसी स्थिति में जहां ट्रायल कोर्ट, पक्षों के संबंधित मामलों और उसके सामने रखे गए दस्तावेजों पर विचार करने पर, यह विचार करता था कि अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा के आदेश के लिए वादी की पात्रता गंभीर संदेह में थी, अपीलीय अदालत ट्रायल जज द्वारा विवेक के प्रयोग में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी जब तक कि ऐसा प्रयोग स्पष्ट रूप से गलत या अस्थिर न पाया गया हो। इस मामले में, ट्रायल जज द्वारा जिन कारणों पर विचार किया गया, उनसे यह संकेत नहीं मिला कि लिया गया दृष्टिकोण संभावित दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए, अपीलीय अदालत को इस मामले में केवल इस आधार पर अपने विचार नहीं रखना चाहिए कि उसकी राय में मामले के तथ्य एक अलग निष्कर्ष की मांग करते हैं। विवेकाधीन आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करते समय क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए ऐसा अभ्यास सही पैरामीटर नहीं है। जब तक ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था, अपीलीय अदालत को इस संबंध में कानून के लगभग तय सिद्धांतों का पालन करते हुए इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। [पैरा 15] [373-एफ-एच; 374-ए-बी] वांडर लिमिटेड बनाम एंटोक्स इंडिया (पी) लिमिटेड 1990 (सप) एस. सी. सी. 727-पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भः

2004 (5) पूरक. एस. सी. आर. 188 पैरा 13 एम. ओ. एच. डी. के लिए संदर्भित है।

मो. मेहताब खान और अन्य बनाम खुशनुमा इब्राहिम और अन्य। 1990 (1) एससीआर 332 पैरा 14 पर निर्भर

1990 (अनुपूरक) scc 727 पैरा 15 पर निर्भर

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 678/2013

2012 की अपील (लॉजिंग) संख्या 412 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 09.10.2012 से।

अपीलकर्ताओं के लिए वी कृष्णमूर्ति, सुबोध के. पाठक, शशि रंजन, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा।

श्याम दीवान, अतुल वाई. चितले, संयुक्ता मुखर्जी, आर.के. उत्तरदाताओं के लिए केनंदा सिंह, अभिजात पी. मेध।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

रंजन गोगोई, जे.

1.अनुमति दी गई.

2. विनिर्दिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (इसके बाद संक्षेप में "एसआर अधिनियम") की धारा 6 के तहत एक मुकदमे में बॉम्बे उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ द्वारा अंतरिम राहत दिए जाने से व्यथित। वर्तमान अपील

मुकदमे में प्रतिवादी 5, 10 और 11 द्वारा दायर की गई है। विशेष रूप से, आक्षेपित आदेश दिनांक 09.10.2012 द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा नियुक्त मुकदमे की संपत्तियों के रिसीवर को कब्जे में रहने और प्रतिवादी नंबर 1 और 2 (वादी) को सौंपने का निर्देश दिया गया है। जिन्हें रिसीवर के एजेंट के रूप में कब्ज़ा करना होगा।

3. मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स की आवश्यक चर्चा शुरू करने से पहले, नीचे बताए गए तरीके से प्रतिस्पर्धी पक्षों की पहचान करना आवश्यक होगा।

नाम	संबंध	ट्रायल कोर्ट में स्थिति
ख़ुशनुमा इब्राहीम	मृतक इब्राहिम खान की पत्नी	वादी क्रमांक 1
रागिब इब्राहिम खान	मृतक इब्राहिम खान का बेटा	वादी क्रमांक 2
श्री असदुल्लाह खान @समीर खान	मृतक इब्राहिम खान का छोटा भाई	प्रतिवादी नंबर 1
श्री नजमुज्जमां खान	मृतक इब्राहिम खान का बड़ा भाई	प्रतिवादी नंबर 2
श्रीमती तारा बेगम	प्रतिवादी नंबर 2 की	प्रतिवादी क्रमांक 3

	पत्नी	
श्री शहरयार खान	प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं 3 का दामाद	प्रतिवादी संख्या 4
मो. महताब खान	मृतक की पहली पत्नी से पुत्र	प्रतिवादी क्रमांक 5
मो. इलियास खान	प्रतिवादी नंबर 3 का भाई	प्रतिवादी संख्या 6
मो. दयान खान	असंबंधित	प्रतिवादी क्रमांक 7
श्रीमती शहजादी	प्रतिवादी संख्या 12 की पत्नी	प्रतिवादी संख्या 8
मिस रानी	असंबंधित	प्रतिवादी संख्या 9
ताबिश इब्राहिम खान	मृतक की दूसरी पत्नी से पुत्र	प्रतिवादी क्रमांक 10
कामरान खान	मृतक की पहली पत्नी से पुत्र	प्रतिवादी क्रमांक 11
जफरुल्लाह खान	मृतक की पहली पत्नी से पुत्र	प्रतिवादी क्रमांक 12

4. वादी नंबर 1 इब्राहिम खान की तीसरी पत्नी होने का दावा करती है जबकि वादी नंबर 2 पहले वादी और इब्राहिम खान का बेटा है। वादी के अनुसार, इब्राहिम खान और पहली वादी की शादी वर्ष 1993 में हुई थी और उक्त विवाह से वादी संख्या 2 का जन्म वर्ष 1996 में किसी समय हुआ था। वादी का दावा है कि वे इब्राहिम खान के साथ फ्लैट नंबर ए-505, नूर-ए-जहां कॉम्प्लेक्स, पाइप रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई में रह रहे थे और उनका कार्यालय 201/202, बिग 3 बिल्डिंग में दूसरी मंजिल, 88, आनंदीलाल पोद्दार मार्ग, मरीन लाइन्स, मुंबई पर भी कब्जा था, जहां से पहली वादी अपना पेशा चला रही थी मेसर्स के.के एसोसिएट्स के नाम पर वकील और सॉलिसिटर।वादी का मामला यह है कि उपरोक्त दोनों संपत्तियां इब्राहिम खान की स्व-अर्जित संपत्तियां थीं और यह कि सूट का फ्लैट पहले वादी के पक्ष में उपहार में दिया गया था, जबकि जहां तक सूट कार्यालय का संबंध है, पहले वादी के पक्ष में एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की गई थी।

5. वादी का अगला मामला यह है कि इब्राहिम खान 28.11.2011 को एक शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली गया था। 1.12.2011 को प्रथम

वादी को पता चल सका कि इब्राहिम खान को ब्रेन हेमरेज हो गया है और वह अस्पताल में भर्ती है।वादी के अनुसार, उन्होंने अगले ही दिन सुबह दिल्ली के लिए उड़ान भरी। हालाँकि, सुबह लगभग 9.30/10.00 बजे इब्राहिम खान की मृत्यु हो गई। इसके बाद, पहले प्रतिवादी (मृतक के भाई) के आग्रह पर मृतक के शव को बिहार के भागलपुर ले जाया गया, जो इब्राहिम खान का मूल स्थान था।वादीगण मृतक के शव को लेकर भागलपुर आये और 4.12.2011 के अपराह्न में उक्त स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। 5.12.2011 को वादी नंबर 1 को उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी नदीम से फोन आया कि सूट के फ्लैट का ताला टूट गया है और कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने एक नया ताला लगा दिया है।वादी के अनुसार, पहली वादी ने अपने घरेलू नौकर निरंजन को बुलाया जिसने उसे सूचित किया कि प्रतिवादी 2, 3 और 4 ने जबरन सूट के फ्लैट पर कब्जा कर लिया है।वादी का यह भी मामला है कि जब उसने अपने कार्यालय से संपर्क किया था तो उसे सूचित किया गया था कि प्रतिवादी नंबर 4 सूट कार्यालय में गया था और कार्यालय के कर्मचारियों से चाबियां छीन ली थीं और परिसर को बंद कर दिया था।

6. वादी के अनुसार, वे 6.12.2011 को मुंबई पहुंचे और सूट फ्लैट पर जाने पर उन्होंने पाया कि वहां नए ताले लगाए गए थे।इसके बाद, उन्होंने 6.12.2011 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद 12.12.2011 को एसआर अधिनियम की धारा 6 के तहत 2012 का मुकदमा संख्या 27 स्थापित किया। 14.12.2011 को, जब मामला न्यायालय द्वारा उठाया गया, तो प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 ने न्यायालय को सूचित किया कि उनका सूट के फ्लैट पर कब्जा नहीं है, लेकिन प्रतिवादी 5, 11 और 12 का कब्जा है।न्यायालय ने दिनांक 14.12.2011 के आदेश द्वारा एक रिसीवर नियुक्त किया और उसे सूट फ्लैट और सूट कार्यालय का निरीक्षण करने और अदालत को वापस रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।ऐसा निरीक्षण न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर द्वारा किया गया था 16.12.2011. निरीक्षण की रिपोर्ट इस आशय से न्यायालय में प्रस्तुत की गई कि प्रतिवादी संख्या 5 से 9 तक सूट फ्लैट पर कब्जा पाया गया। हालाँकि, कोर्ट रिसीवर कार्यालय परिसर के दरवाजे खोलने में सफल नहीं हुआ क्योंकि वहाँ आगे ताले लगे हुए थे और पूछताछ में यह संकेत नहीं मिला कि चाबियाँ किसके पास थीं।तदनुसार, कोर्ट रिसीवर ने कोर्ट को सूचित किया कि वाद कार्यालय का औपचारिक कब्ज़ा नहीं लिया जा सका। उपरोक्त परिस्थितियों में, वादी के कहने पर, प्रतिवादी 5 से 12 को मुकदमे में पक्षकार बनाया गया।

7. इस स्तर पर प्रतिवादियों के विद्वान ट्रायल जज के समक्ष पेश किए गए विशिष्ट मामले पर ध्यान दिया जा सकता है। तथ्य यह है कि पहली वादी इब्राहिम खान की तीसरी पत्नी थी और दूसरी वादी उक्त विवाह से पैदा हुआ बेटा था, प्रतिवादियों द्वारा विवादित नहीं है।वादपत्र में बताई गई परिस्थितियों में इब्राहिम खान की मृत्यु भी विवाद में नहीं है। प्रतिवादियों के अनुसार, अपीलकर्ता वर्ष 2009 के मध्य तक मृतक इब्राहिम खान के साथ मुकदमा परिसर में रह रहे थे, जब पहला वादी मृतक से अलग हो गया था।इसके बाद, प्रतिवादियों के अनुसार, वादी सूट फ्लैट पर कब्जे में नहीं थे और इसके बजाय, मीरा रोड पर पहले वादी के पिता के घर में रह रहे थे।दूसरा वादी मीरा रोड स्थित एक स्कूल में पढ़ता था।यह प्रतिवादियों का विशिष्ट मामला है कि मृतक, प्रासंगिक समय पर, पहली पत्नी (प्रतिवादी संख्या 5) से अपने बेटे के साथ सूट फ्लैट में रह रहा था और प्रतिवादियों को इब्राहिम खान की मृत्यु पर सूट फ्लैट विरासत में मिला था।जहां तक वाद कार्यालय का संबंध है, यह प्रतिवादियों का विशिष्ट मामला है कि वादी संख्या 1 का उक्त परिसर पर कब्जा नहीं था और उक्त वादी संख्या 1 किसी अन्य स्थान पर स्थित दुकान नंबर 32/33 अशोका सेंटर, दूसरी मंजिल, एल.टी. मार्ग, मुंबई कार्यालय से कार्य कर रहा था

8. पक्षों की संबंधित दलीलों के साथ-साथ विद्वान ट्रायल जज के समक्ष विस्तृत दस्तावेज रखे गए थे, जिसके आधार पर संबंधित पक्षों द्वारा संबंधित तारीख पर सूट फ्लैट और सूटऑफिस के कब्जे में होने का दावा

करते हुए दलीलें पेश की गईं। उन राहतों को उचित ठहराएँ जो संबंधित पक्ष न्यायालय से चाह रहे थे।जैसा कि उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ के आदेश से स्पष्ट है, जहां तक मुकदमे के फ्लैट का संबंध है, वादी ने 50 से अधिक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिनका विवरण दिनांक 9.10.2012 के आदेश में कालानुक्रमिक क्रम में सूचीबद्ध किया गया है।जहां तक सूट ऑफिस का सवाल है, इसी तरह, वादी ने कब्जे के अपने दावे को दिखाने के लिए 31 दस्तावेजों पर भरोसा किया था।इसी तरह, प्रतिवादियों ने यह दिखाने के लिए दस्तावेजों की समान रूप से लंबी और विस्तृत सूची पर भी भरोसा किया था कि वादी के पास संबंधित समय पर सूट फ्लैट और सूट कार्यालय का कब्जा नहीं था, जैसा कि दावा किया गया है।चूंकि उक्त दस्तावेजों के विवरण पर उच्च न्यायालय की दोनों पीठों द्वारा सूक्ष्मता से ध्यान दिया गया है, इसलिए इस न्यायालय के लिए मामले के उक्त पहलू पर एक बार फिर से विचार करना आवश्यक नहीं है।इसके बजाय, हम उन कारणों पर संक्षेप में गौर कर सकते हैं जिनके कारण विद्वान ट्रायल जज ने वादी को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था और जो कारण अपीलीय पीठ पर हावी हो गए थे और उन्होंने विद्वान ट्रायल जज के उक्त आदेश को पलट दिया था।

9. विद्वान ट्रायल जज और अपीलीय न्यायालय दोनों ने वादी के अधिकार के संबंध में अपने-अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रतिस्पर्धी पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए समान दस्तावेजों पर विचार किया। विशेष

रूप से, विद्वान ट्रायल जज ने वादी द्वारा दायर बेदखली की घटनाओं के विवरण पर चर्चा की थी और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसे कुछ हद तक अविश्वसनीय और असंगत माना था कि प्रतिवादी नंबर 1 (मृतक इब्राहिम खान का बेटा) जो है कथित तौर पर मृतक इब्राहिम खान के दाह संस्कार के संबंध में भागलपुर में प्रासंगिक समय पर वादी को बेदखल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संबंध में प्रतिवादी 2 से 4 के दावे पर कि वे भी प्रासंगिक समय पर भागलपुर में थे, विद्वान ट्रायल जज द्वारा विचार किया गया। कथित तौर पर वादी नंबर 1 को उसके पड़ोसियों और उसकी घरेलू सहायता द्वारा सुनाई गई घटना के संस्करण भी कुछ हद तक विरोधाभासी पाए गए। विद्वान ट्रायल जज ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि मीरा रोड के स्कूल में दूसरे वादी द्वारा पढ़ाई का मुकदमा चलाने और मीरा रोड पर वादी नंबर 1 के माता-पिता के साथ रहने के संबंध में वादी का बयान प्रत्युत्तर में रिकॉर्ड पर लाया गया था और यह वादी मामले का हिस्सा नहीं था।मामले में अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि वादी नंबर 1 के विजिटिंग कार्ड में एक अन्य पता दिखाया गया था मुकदमा कार्यालय की तुलना में और यह तथ्य भी कि बॉम्बे बार एसोसिएशन में वादी नंबर 1 की अस्थायी सदस्यता को सूचित करने वाला संचार मुकदमे के फ्लैट पते पर भेजा गया था, जिसे "स्थानांतरित" टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया था। तथ्य यह है कि अशोक केंद्र में कार्यालय का पता दर्शाने वाले

वादी के विजिटिंग कार्ड में वादी के वही टेलीफोन नंबर थे जिनका उल्लेख बैंक के कुछ संचारों में किया गया था, विद्वान ट्रायल न्यायाधीश द्वारा विधिवत नोट किया गया था। उपरोक्त संदर्भ में वादी नंबर 1 का यह दावा कि उक्त विजिटिंग कार्ड एक जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज है, मुकदमे के मुकदमे में निर्णय के लिए उपयुक्त मुद्दा माना गया था। विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने वर्ष 2009 में जारी किए गए दोनों वादी के पासपोर्ट को ध्यान में रखा, जिसमें मुकदमा परिसर के पते के साथ-साथ वाउचर/मेमो भी दिखाया गया था। सूट के फ्लैट में पाए गए घरेलू और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए वादी नंबर 1 द्वारा भुगतान दिखाया गया। उपरोक्त तथ्यों और उनके समर्थन में रखे गए दस्तावेजों पर समग्र रूप से विचार करने पर, विद्वान ट्रायल जज का विचार था कि वादी के मामले में विसंगतियां और असंभवताएं थीं जिन्हें मुकदमे के परीक्षण में स्थापित करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, जैसा कि वादी द्वारा दावा किया गया था, कब्जे में वापस रखने के निर्देश की अंतरिम राहत को अस्वीकार कर दिया गया था।

10. अपीलीय न्यायालय ने विद्वान ट्रायल न्यायाधीश द्वारा विचार किए गए उन्हीं दस्तावेजों को पूरी तरह से अलग तरीके से समझा।विशेष रूप से, यह माना गया कि 16.12.2011 को रिसीवर द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान सूट फ्लैट में पाए गए विभिन्न घरेलू और इलेक्ट्रॉनिक सामान साबित हुए कि वादी द्वारा 22.8.2008 के चालान/वाउचर के आधार

पर खरीदा गया था। और उक्त तथ्य ने वादी द्वारा सूट फ्लैट के कब्जे की ओर इशारा किया और वास्तव में, प्रतिवादियों के मामले को ध्वस्त कर दिया कि पहले वादी और मृतक कैलेंडर वर्ष 2009 के मध्य में कुछ समय के लिए अलग हो गए थे। 2009 में वादी को जारी किए गए पासपोर्ट में सूट के फ्लैट का पता दर्ज किया गया था; वादी संख्या 1 का एचडीएफसी बैंक विवरण; प्रासंगिक समय के दौरान वादी नंबर 1 के आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, सूट फ्लैट के पते को इंगित करने वाले सभी पर अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विधिवत भरोसा किया गया था।अपीलीय न्यायालय ने 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 11.8.2011 को दूसरे वादी द्वारा प्रस्तुत (अपीलीय न्यायालय के समक्ष) आवेदन पत्र पर भी भरोसा किया। एच.आर. कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स दिनशॉ वाचा रोड, चर्च गेट, मुंबई में जिस पर खुद मृतक इब्राहिम खान ने सूट कार्यालय और सूट फ्लैट का पता देते हुए हस्ताक्षर किए थे। वादी का कथन है कि अशोका सेंटर में उसके कार्यालय को दर्शाने वाला विजिटिंग कार्ड एक जाली दस्तावेज था और यह भी दावा है कि वादी ने उक्त परिसर का उपयोग अस्थायी रूप से किया था क्योंकि मुकदमा कार्यालय नवीकरण के अधीन था, जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए रुख का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण के रूप में स्वीकार किया था।उपरोक्त आधार पर विद्वान ट्रायल जज के आदेश को पलटने के लिए उपयुक्त पाया गया और वादी को

अंतरिम राहत देने से इनकार को अनुचित माना गया। तदनुसार, अपील में अंतरिम राहत दी गई।

11. हमने अपीलकर्ताओं के वरिष्ठ वकील श्री वी. कृष्णमूर्ति और उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 के वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान को सुना है।

12. विनिर्दिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 6 के तहत कार्यवाही का उद्देश्य एक सारांश कार्यवाही है जिसका उद्देश्य वहन करना है पीड़ित पक्ष को उस कब्जे को पुनः प्राप्त करने के लिए एक तत्काल उपाय, जिस पर बेदखली के अवैध कार्य द्वारा उसे अन्यायपूर्ण ढंग से वंचित किया गया हो।धारा 6 के तहत एक मुकदमे में निर्णय के लिए स्वामित्व या कब्जे के बेहतर अधिकार का प्रश्न नहीं उठता है, जहां निर्णय लेने के लिए आवश्यक एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या वादी मुकदमा दायर करने की तारीख से छह महीने पहले किसी भी समय कब्जे में था।एसआर अधिनियम की धारा 6 में अंतर्निहित विधायी चिंता अवैध बेदखली के मामलों में त्वरित उपाय प्रदान करना है ताकि वादियों को कानून के क्षेत्र के बाहर उपचार खोजने से हतोत्साहित किया जा सके।यह धारा 6(3) के प्रावधानों से स्पष्ट है जो ऐसे मुकदमे में पारित डिक्री के खिलाफ अपील या यहां तक कि समीक्षा के उपाय पर रोक लगाता है।

13. जबकि एसआर अधिनियम की धारा 6(3) के तहत रोक प्रारंभिक फोरम को ध्यान में रखते हुए तत्काल मामले पर लागू नहीं हो सकती है

जिसमें मुकदमा दायर किया गया था और अंतरिम आदेश से उत्पन्न होने वाली अपील पत्र पेटेंट के तहत जारी की गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट, जैसा कि इस न्यायालय की संविधान पीठ ने पी.एस. एलआरएस बनाम आंध्रा बैंक लिमिटेड और अन्य 1 द्वारा सथप्पन (मृत), विडंबना यह है कि पार्टियों के अंतरिम अधिकार के संबंध में पारित आदेश की शुद्धता संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय तक पहुंच गई है।आमतौर पर और सामान्य प्रक्रिया में, इस समय तक मुकदमे का निपटारा हो जाना चाहिए था। दुख की बात है कि मुकदमे का कोई तार्किक निष्कर्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है और सिस्टम में व्याप्त लौकिक देरी के कारण ही अंतरिम मामलों को अंतिम अदालत में बहुत ही जोश और उत्साह के साथ लड़ा जा रहा है। स्थिति की जमीनी हकीकत को देखते हुए यह विचार करना न तो संभव है और न ही व्यावहारिक है कि अंतरिम मायने रखता है, भले ही वे हों मुख्य मुकदमे के गुणों के साथ अटूट रूप से जुड़ा हो सकता है, इसका उत्तर हमेशा सख्त तटस्थता बनाए रखते हुए दिया जाना चाहिए, अर्थात् निर्णय लेने से इंकार कर दिया जाना चाहिए।अदालतों का ऐसा रुख न तो संभव है और न ही व्यावहारिक। इसलिए, अदालतों को उन मुद्दों पर विचार करके अंतरिम मामलों पर निर्णय लेने का साहस करना होगा जो मुकदमे की पूरी सुनवाई में निर्णय के लिए सबसे अच्छे हैं। इस तरह के कार्य को करने में अंतर्निहित जोखिम को देखते हुए, जो ज्यादातर मामलों में नाजुक हो जाता है, अदालतों को इस संबंध में जिन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, उन्हें

कुछ विस्तार से बताया जाना आवश्यक है, हालांकि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों को फंसाया नहीं जा सकता है। किसी स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूले या किसी सटीक निर्धारित मानदंड के भीतर।अदालतों को यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि क्या मुख्य मुकदमे में शामिल मुद्दों के अलावा अन्य मुद्दों पर विचार करने पर अंतरिम राहत दी जा सकती है और क्या आंशिक अंतरिम राहत मामले के अंतिम निपटान तक न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।यदि वादी मुकदमा हार जाता है तो प्रतिवादी पर निषेधाज्ञा देने के परिणामों के साथ-साथ वादी पर होने वाले परिणामों के साथ-साथ जहां निषेधाज्ञा अस्वीकार कर दी जाती है लेकिन अंततः मुकदमा डिक्री हो जाता है, हर मामले में न्यायालय द्वारा सावधानीपूर्वक विचार और संतुलित किया जाना चाहिए।अंतरिम राहतें, जो सुनवाई-पूर्व आदेश के समान होती हैं, से बचना चाहिए जहाँ भी संभव हो।हालांकि अनुभव से पता चला है कि इस आशय की टिप्पणियाँ और स्पष्टीकरण कि दर्ज किए गए निष्कर्ष प्रथम दृष्टया और अस्थायी हैं, केवल पार्टियों के अंतरिम अधिकार को तय करने के लिए हैं या इरादा है, अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं और मुख्य मुकदमे से संबंधित मुद्दों पर अंतरिम निष्कर्षों से पता चला है अंतिम निर्णय की प्रक्रिया में प्रभाव यह है कि न्यायिक अनुशासन का सख्त अभ्यास काफी मदद और सहायता करेगा।आत्म-सुधार की शक्ति और वरिष्ठ मंचों के आदेशों को उचित परिप्रेक्ष्य में समझने से उन मुद्दों पर अंतरिम मामले का निर्णय लेने में निहित खतरों को हल करने में काफी

मदद मिलेगी, जिनका मुख्य मुकदमे में उत्पन्न होने वाले मुद्दों के साथ घनिष्ठ संबंध हो सकता है।

14. वर्तमान अपील में उठने वाले मुद्दों का एक और आयाम है। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ द्वारा वादी को दी गई अंतरिम राहत वादी को कब्जा सौंपने के लिए एक अनिवार्य निर्देश है। अनिवार्य अंतरिम राहत देने के लिए न्यायालय की उच्चतम स्तर की संतुष्टि की आवश्यकता होती है; यह निषेधात्मक निषेधाज्ञा देने वाले मामले से कहीं अधिक है।वास्तव में, यह एक दुर्लभ शक्ति है, जिसके शासी सिद्धांतों को शायद ही दोहराने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा दोराब कावासजी वार्डन बनाम कूमी सोराब वार्डन और अन्य 2 में जो सिद्धांत विकसित किए गए थे, वे हमारे न्यायशास्त्र में दृढ़ता से अंतर्निहित हो गए हैं।दोराब कैवासजी वार्डन (सुप्रा) में फैसले के पैरा 16 और 17, नीचे दिए गए हैं, इस संबंध में उपयोगी रूप से याद किए जा सकते हैं:

> "16. इस प्रकार अंतःविषय अनिवार्य निषेधाज्ञा की राहत आम तौर पर अंतिम गैर-विवादित स्थिति की यथास्थिति को बनाए रखने या बहाल करने के लिए दी जाती है, जो अंतिम सुनवाई तक लंबित विवाद से पहले थी जब पूर्ण राहत दी जा सकती है या उन कार्यों को पूर्ववत करने के लिए बाध्य किया जा सकता है जो अवैध रूप से

किए गए हैं या जो शिकायत करने वाले पक्ष से गलत तरीके से लिया गया था उसे बहाल किया जा सकता है। लेकिन किसी पक्ष को ऐसा निषेधाज्ञा देने के बाद से जो विफल रहता है या मुकदमे में अपना अधिकार स्थापित करने में विफल रहने पर उस पक्ष को बहुत बड़ा अन्याय या अपूरणीय क्षति हो सकती है जिसके विरुद्ध यह अधिकार दिया गया था या वैकल्पिक रूप से उस पक्ष को इसे न देने से जो सफल होता है या सफल होगा, समान रूप से बहुत बड़ा अन्याय या अपूरणीय क्षति हो सकती है, अदालतें विकसित हुई हैं दिशानिर्देशों में प्रमाणित करें। आम तौर पर कहा गया है कि ये दिशानिर्देश हैं:

(1) वादी के पास मुकदमे के लिए एक मजबूत मामला है। वह यह है कि यह प्रथम दृष्टया उच्च मानक का होगा। मामला जो आम तौर पर एक निषेध के लिए आवश्यक है निषेधाज्ञा।

(2) अपूरणीय को रोकना आवश्यक है या गंभीर चोट जो आम तौर पर धन के संदर्भ में क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती।

(3) सुविधा का संतुलन उस व्यक्ति के पक्ष में है जो इस तरह की राहत चाहता है।

17. अनिवार्य रूप से एक न्यायसंगत राहत होने के नाते एक अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा का अनुदान या इनकार अंततः अदालत के ठोस न्यायिक विवेक पर निर्भर करेगा, जिसका प्रयोग प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में किया जाएगा।यद्यपि उपरोक्त दिशानिर्देश न तो संपूर्ण हैं और न ही पूर्ण या पूर्ण नियम हैं, और कार्रवाई की आवश्यकता वाले असाधारण मामले भी हो सकते हैं, ऐसे निषेधाज्ञा देने या अस्वीकार करने के लिए उन्हें पूर्व शर्त के रूप में लागू करना न्यायिक विवेक का एक अच्छा अभ्यास होगा।''

15. ऐसी स्थिति में जहां पक्षों के संबंधित मामलों और उसके समक्ष रखे गए दस्तावेजों पर विचार करने पर विद्वान ट्रायल कोर्ट का विचार था कि अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा के आदेश के लिए वादी की पात्रता गंभीर संदेह में थी, अपीलीय न्यायालय विद्वान ट्रायल न्यायाधीश द्वारा विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था जब तक कि ऐसा प्रयोग स्पष्ट रूप से गलत या अस्थिर न पाया गया हो।पहले से ही विद्वान ट्रायल जज द्वारा बताए गए कारणों पर विचार किया जा रहा है ध्यान दें, हमारे अनुसार, यह

इंगित न करें कि लिया गया दृश्य संभावित दृष्टिकोण नहीं है।इसलिए, अपीलीय अदालत को इस मामले में केवल इस आधार पर अपने विचार नहीं रखना चाहिए कि उसकी राय में मामले के तथ्य एक अलग निष्कर्ष की मांग करते हैं। विवेकाधीन आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करते समय क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए ऐसा अभ्यास सही पैरामीटर नहीं है। हालाँकि हमें यह नहीं समझा जाना चाहिए कि अपीलीय न्यायालय अपने निष्कर्षों में गलत था, इस बात पर ज़ोर देने की कोशिश की गई है कि जब तक ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था, तब तक अपीलीय न्यायालय को निम्नलिखित में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। इस संबंध में कानून के वस्तुतः स्थापित सिद्धांत वांडर लिमिटेड बनाम एंटॉक्स इंडिया (पी) लिमिटेड मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं। उपरोक्त निर्णय का 3 पैरा 14 जो नीचे दिया गया है, स्थिति को काफी हद तक सारांशित करेगा:

> "14. डिवीजन बेंच के समक्ष अपीलें एकल न्यायाधीश द्वारा विवेक के प्रयोग के खिलाफ थीं। ऐसी अपीलों में, अपीलीय अदालत प्रथम दृष्टया न्यायालय के विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगी और अपने विवेक को प्रतिस्थापित करेगी, सिवाय इसके कि जहां विवेकाधिकार हो यह दिखाया गया है कि इसका उपयोग मनमाने ढंग से, या मनमाने ढंग से या विकृत तरीके से किया गया है या जहां

अदालत ने इंटरलोक्यूटरी निषेधाज्ञा के अनुदान या इनकार को विनियमित करने वाले कानून के स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की है।विवेक के प्रयोग के विरुद्ध अपील को सैद्धांतिक रूप से अपील कहा जाता है। अपीलीय अदालत सामग्री का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगी और नीचे की अदालत द्वारा पहुंचाए गए निष्कर्ष से भिन्न किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश नहीं करेगी यदि उस अदालत द्वारा पहुंचा गया निष्कर्ष सामग्री पर उचित रूप से संभव हो।अपीलीय अदालत को आम तौर पर केवल इस आधार पर अपील के तहत विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा कि यदि उसने मुकदमे के चरण में मामले पर विचार किया होता तो यह एक विपरीत निष्कर्ष पर आता।यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा विवेक का प्रयोग उचित रूप से और न्यायिक तरीके से किया गया है, तो यह तथ्य कि अपीलीय अदालत ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया होगा, ट्रायल कोर्ट के विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।इन सिद्धांतों का उल्लेख करने के बाद गजेंद्रगडकर, जे. प्रिंटर्स (मैसूर) प्राइवेट लिमिटेड बनाम पोथन जोसेफ: (एससीआर 721) में

"... ये सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैं, लेकिन जैसा कि विस्काउंट साइमन ने चार्ल्स ओसेंटन एंड कंपनी बनाम झानाटन मामले में देखा है... नीचे एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश की अपील की अदालत द्वारा उलटफेर के बारे में कानून उसके विवेक का प्रयोग अच्छी तरह से स्थापित है, और जो भी कठिनाई उत्पन्न होती है वह केवल एक व्यक्तिगत मामले में अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के आवेदन के कारण होती है।"

अपीलीय निर्णय इस सिद्धांत को स्थगित करता प्रतीत नहीं होता है।

16. यद्यपि उपरोक्त चर्चा हमें इस निष्कर्ष पर ले जाएगी कि उच्च न्यायालय की विद्वान अपीलीय पीठ विद्वान ट्रायल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने में सही नहीं थी, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा उपरोक्त निष्कर्ष अभिव्यक्ति नहीं है पार्टियों के बीच विवाद के गुण-दोष पर हमारी राय।डिवीजन बेंच के विचार से हमारी असहमति पूरी तरह से इस आधार पर है कि अपीलीय शक्ति के प्रयोग का तरीका वांडर लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं है।तदनुसार, हमने बॉम्बे उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ द्वारा पारित दिनांक 09.10.2012 के आदेश को रद्द कर दिया है और विद्वान

ट्रायल जज के दिनांक 13.04.2012 के आदेश को बहाल करते हुए हम विद्वान ट्रायल जज, या ऐसी अन्य अदालत से अनुरोध करते हैं जिसके पास मामला है। इस बीच, मुख्य मुकदमे को शीघ्रता से निपटाने के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है क्योंकि इसका कैलेंडर इस उम्मीद के साथ अनुमति देगा कि यह इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर संभव होगा।अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

के.के.टी.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दिव्या शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।